भारतीय जनता पार्टी

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 06 मार्च, 2013

संसद के संयुक्त अधिवेशन को अपने संबोधन में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में श्री अरुण जेटली द्वारा रखी गई प्रमुख बातें

यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपनी छाप छोड़ने के लिए किसी भी सरकार कानौ वर्ष का कार्यकाल एक अच्छा खासा समय होता है। इतने समय में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनसे देश की तकदीर पर असर पड़ सके। यूपीए का निराशाजनक रिकॉर्ड रहा है। उसे एक उत्साही राष्ट्र का शासन विरासत में मिला था। दुनिया भारत को एक निवेश स्थल के रूप में देखती थी। एनडीए ने सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 8.4 प्रतिशत पर छोड़ी थी। अर्थव्यवस्था की स्थिति उस समय मजबूत थी। यूपीए सरकार अब शासन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है, लेकिन भारत विश्व के नक्शे में कहीं नहीं है जैसा कि वह एक दशक पहले था। ब्रिक्स में 'आई' के हटने का खतरा पैदा हो गया है। चारों तरफ निराशा और शासन के प्रति अविश्वास का माहौल है। इसके अलावा नीतियों का अभाव और बदलाव की चाह है।

यूपीए ने एक उत्साही राष्ट्र को निराशाजनक राष्ट्र में कैसे बदला?

यूपीए का शासन मॉडल

मैंने बार–बार इस बात को कहा है कि यूपीए का शासन मॉडल विश्व के सबसे पहले लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। स्वाभाविक रुप से प्रधानमंत्री पार्टी का नेता होता है। ऐसा मॉडल जहां कंपनी के संबंध में बोर्ड फैसले करता है और भाड़े का एक सीईओ उसे प्रभाव में लाता है, कार्पोरेट शसन के लिए तो यह व्यवस्था ठीक है लेकिन किसी देश का शासन चलाने के लिए अनुचित है। प्रधानमंत्री की राजनैतिक शक्ति के अभाव के परिणाम हैं :–

- नेतृत्व का संकट
- लकवाग्रस्त नीति
- गलती करने वाले मंत्रियों और भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं

सरकार में नेतृत्व का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पिछले 9 वर्ष में नीतिगत फैसले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसी ऐसी संस्था ले रही है जिसका संविधान में कोई अस्तित्व नहीं है। बिना सोचे–समझे बनाई गई, अनेक नीतियां जैसे बैंक ऋण माफी और मनरेगा के कार्यान्वयन के मुद्दे के परिणामस्वरुप आर्थिक

परिदृश्य में वर्तमान में निराशा व्याप्त है। बैंक ऋण माफी ऐसे लोगों को दी गई जो इसके हकदार नहीं थे। मनरेगा में कई राष्ट्रीय संसाधन झोंक दिए गए, लेकिन संपत्ति का सृजन नहीं हो पाया।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

इस बात में कहीं कोई मत–भिन्नता नहीं है कि भारत में विकास की जरुरत है। भारत कम विकास दर का खतरा नहीं उठा सकता और न ही लोगों को लुभाने वाले गरीबी हटाओ जैसे नारे सह सकता है जैसाकि आजादी के बाद पहले चार दशकों में हुआ था। भारत को अधिक विकास दर की, अधिक आर्थिक गतिविधि, रोजगार सृजन, बेहतर बुनियादी ढांचे और गरीबी हटाओ योजनाओं के लिए अधिक राजस्व की जरुरत है। यूपीए, जिसे विरासत में 8.4 प्रतिशत की विकास दर मिली थी वह 9 प्रतिशत की विकास दर बरकरार रखने के बजाय अर्थव्यवस्था की विकास दर को 5 प्रतिशत से भी कम पर कैसे ले आया? 5 प्रतिशत की विकास दर पर अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियां सृजित नहीं कर सकती, न ही वह गरीबी के अभिशाप से लड़ सकती है।

भारत को खेती में लगे अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को निर्माण क्षेत्र में तब्दील करना होगा। उसे एक कम लागत वाले उत्पादन हब में बदलना होगा। उत्पादन की हमारी विकास अवस्था 12 से 14 प्रतिशत होनी चाहिए। तभी हम जीडीपी के 25 प्रतिशत पर कब्जा करे निर्माण क्षेत्र का लक्ष्य तय कर सकते हैं। इसके लिए आपको तत्काल एक व्यापक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम घोषित करना होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की गति धीमी क्यों हो गई? हमारे ठेकेदारों को राजमार्ग कार्यक्रमों से हटाया क्यों जा रहा है? एनएचएआई ऐसा संगठन क्यों बन गया है जिससे निपटना कठिन है ? हाईवे डेवलपर्स नई परियोजनाओं की निविदा के लिए तैयार नहीं हैं।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को पिछले वर्ष लगभग त्याग दिया गया। इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था जबकि 8,000 करोड़ रुपये ही खर्च किये गए।
- कोयला खदान आबंटन में हुआ भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है। बिजली संयंत्र कोयले की कमी से जूझ रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियम द्वारा एनडीए के समय में विद्युत क्षेत्र ने जो सफलता अर्जित की वह अब संकट से जूझ रहा है।
- दूरसंचार क्षेत्र जिसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था उसका अब कोई खरीदार नहीं बचा। भारतीय दूरसंचार अब बिक्री योग्य नहीं रहा।
- बजट में शायद ही ऐसा कुछ है जिससे कृषि या निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।
- मंत्रियों की आपसी तकरार के कारण 7 लाख करोड़ रूपये की परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं।
- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

- पूर्वोत्तर विकास जनांकिकी परियोजनाएं अस्तित्व में नहीं हैं। पूर्वोत्तर की अनदेखी हो रही है। यूपीए घुसपैठियों के जरिये जनांकिकी का स्वरूप बदलने से संतुष्ट है। उसकी प्राथमिकता जनांकिकी के बदलते स्वरूप में है न कि विकास अभियानों में।
- सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने, स्वच्छता के सार्वभौमिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय संसाधनों को बर्बाद करके पिछले कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण यूपीए ने देश को कर्ज के बोझ के नीचे दबा दिया है। सामाजिक क्षेत्र की सभी योजनाओं का पुनर्गठन किया गया ताकि वित्तीय घाटे को और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके, पूंजीगत खर्च को कम करके 93,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के लिए मामूली धनराशि बची है। इसमें केवल 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। मनरेगा और ग्रामीण सड़कों के लिए अनुदान में पर्याप्त कटौती कर दी गई। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना अगले वर्ष के लिए केवल 5601 करोड़ रुपये प्रदान की गई है।
- खाद्य सुरक्षा विधेयक एक दिवास्वप्न बना हुआ है। इसमें सबको खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ मॉडल को छोड़ दिया गया है। पिछले साल 75,000 करोड़ रुपये की खाद्य सुरक्षा का प्रस्ताव किया गया था लेकिन वास्तव में 85,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया। अगले वर्ष के लिए 5000 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गई है (10,000 करोड़ रुपये नहीं) यानी 85,000 करोड़ रुपये +10,000 करोड़ रुपये)। नयी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा के बारे में केवल चर्चा होती है। इसके विपरीत एनडीए शासित कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। बिहार में जीडीपी विकास दर कम से कम 12 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में विकास दर दहाई के आंकड़े पर है। मध्य प्रदेश और गुजरात में कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है।

<u>भ्रष्टाचार</u>

सरकार का नेतृत्व नियंत्रण में नहीं होने के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार यूपीए के प्रदर्शन का हॉलमार्क बन गया है। यूपीए में कई तरह के मंत्री हैं, कुछ अहंकारी हैं, कुछ बेहद भ्रष्ट हैं, कुछ बाल की खाल निकालते हैं और कई तो कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ अक्सर भारी भूल करते हैं। गुलदस्ते की जगह गुलदान ने ले ली है। भ्रष्टाचार के कारण भारत में निवेश के अवसर कम हुए हैं। भारत में न केवल अंतर्राष्ट्रीय निवेशक निवेश करने से कतरा रहे हैं बल्कि घरेलू निवेशक भी विश्व में और कहीं निवेश करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। धन के बाहर जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।

राष्ट्रमंडल खेलों में खेलकूद और पर्यटन से भारत को लाभ होना चाहिए था लेकिन उसे भ्रष्टाचार के रूप में याद किया जा रहा है। यूपीए के नेता जेल भेज दिये गए और देश का खेलकूद का माहौल खराब हो गया।

2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए एक केन्द्रीय मंत्री और अन्य को जेल जाना पड़ा। बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय संसाधन बर्बाद हुए हैं। दूरसंचार की सफलता की कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। कोयला खान आबंटन घोटाले में बेशकीमती राष्ट्रीय संसाधनों को मनमानी कीमत पर आबंटित कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा और बिजली संयंत्रों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में रिश्वत के मामले की अब लीपापोती की जा रही है। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि किसने यह रिश्वत ली। उसे दंडित करना चाहिए। सरकार सच्चाई का पता लगाने के नाम पर इस मामले को महज एक संसदीय समिति को सौंपकर पल्ला झाड़ना चाहती है। सांसदों को छानबीन करने, हिरासत में पूछताछ करने या अनुरोध पत्र प्राप्त करने हक नहीं है।

देश में एक मजबूत जवाबदेही प्रणाली की राष्ट्रीय आकांक्षा को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए। लोकपाल विधेयक को लोकसभा में हड़बड़ी में पारित कराया गया लेकिन राज्य सभा में सरकार द्वारा अड़चन डाल दी गई। प्रवर समिति के जरिये विधेयक को सुधारने के हमारे प्रयासों में सरकार ने बाधाएं खड़ी की। कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को नहीं माना गया।

- अगर दोषी अधिकारी को जांच शुरु करने से पहले लोकपाल के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा तो जांच की गोपनीयता और शीघ्रता खत्म हो जाएगी।
- लोकपाल की इजाजत के बिना सरकार द्वारा किसी जांच अधिकारी का तबादला क्यों किया जाना चाहिए?
- जांच एजेंसी के प्रमुख जैसे सीबीआई को बिना किसी भय या पक्षपात के काम करना चाहिए। उसके कार्यकाल की एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति के बाद और कोई पद मिलने का प्रलोभन नहीं होना चाहिए।

अब समय आ गया है कि भारत की राजनीति कुछ गंभीरता दिखाए और भ्रष्ट लोगों को शीघ्र दंडित करना शुरु करे।

आतंकवाद, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा

कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हाल ही में वहां शांति लौटी है। भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में सीमा पार से किसी प्रकार की बातचीत या सुझाव पर गौर नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति हमारी नीति हमेशा करुणा और सहानुभूति की होनी चाहिए। हमारा प्रयास विकास और अखंडता होना चाहिए। हमें जन–समर्थक और अलगाववादियों का विरोधी होना चाहिए।

संसद पर 2001 में हमले के दोषी को फांसी दिये जाने पर घाटी के नेताओं ने हाल में जिस तरह की प्रतिक्रिया दी वह परेशान करने वाली है। भारत एक कमजोर देश नहीं है और वह कोई ऐसा संकेत नहीं दे सकता कि अलगाववादियों के दबाव में है।

माओवादी भारत के लोकतंत्र को छिन्न–भिन्न करने पर आमादा हैं।

माओवादी हिंसा के जरिये हमारे संसदीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की धमकियां दे रहे हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों का शोषण कर रहे हैं। हमें एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा अवश्य करनी चाहिए कि राष्ट्रीय संसाधनों पर पहला हक आविदासी क्षेत्रों का होना चाहिए लेकिन उन क्षेत्रों के विकास के लिए हमें पर्याप्त स्वीकार्य कानून और व्यवस्था की जरुरत है। पर्याप्त सुरक्षा तंत्र के साथ विकासात्मक अभियान की माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकमात्र उपाय है।

हैदराबाद विस्फोट

हैदराबाद के हाल के विस्फोट में अनेक निर्दोषों की जानें गईं और अनेक घायल हो गए। आतंकवाद को रोकने का एकमात्र तरीका मजबूत गुप्तचर व्यवस्था और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना है। गुप्तचर और सुरक्षा बल की शत–प्रतिशत सफलता का रिकॉर्ड होना चाहिए। आतंकवादियों को केवल एक बार कामयाबी से मतलब होता है। क्या हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने पर्याप्त जानकारी होते हुए भी उसकी उपेक्षा कर दी? क्या हमें हैदराबाद की पूरी तरीके से स्वच्छता की जरुरत है ? हैदराबाद विस्फोट इस बात की याद दिलाता है कि हम अपनी रक्षा को कम नहीं कर सकते। आतंकवाद का मुकाबला केन्द्र और राज्यों को मिलकर करना है। आतंकवाद और संघीय ढांचे को लेकर चल रही काल्पनिक बहस से बचा जाना चाहिए। दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसी आधार पर एनसीटीसी का गठन हो सकता है।

भारत और पड़ोसी देश

भारत ने अपने पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं लेकिन हमारी इच्छा है कि पडोस में स्थिरता बनी रहे।

पाकिस्तान एक अस्थिर देश है। उसकी स्थिति ऐसी है कि कोई जहां पर्यवेक्षक भी समझ पाने में नाकाम हैं कि देश का नियंत्रण किसके हाथ में है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। मुझे विश्वास है कि हाल में जो उकसावे वाली कार्रवाई हुई है उसके कारण उन्होंने अपनी इच्छाओं को पीछे धकेल दिया होगा।

नेपाल भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण देश है। संस्कृति और धर्म के लिहाज से हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। वहां का संवैधानिक संकट हमारे लिए चिंता का विषय है।

बंगलादेश के राजनेताओं के साथ भारत के दोस्ताना संबंध रहे हैं। इस समय जो माहौल है उसमें अनेक लंबित मुद्दों को इस तरीके से सुलझाया जा सकता है जो हमारे देश की जनता को भी स्वीकार्य होगा।

श्रीलंका भारत का पुराना मित्र है। हमारे सैनिकों ने श्रीलंका में शांति बहाली के लिए खून बहाया है। हमारा श्रीलंका के साथ संबंध बनाए रखना स्वाभाविक है क्योंकि श्रीलंका में मानवाधिकार के उल्लंघन का सीधा असर तमिलनाडु और बाकी जगहों पर पड़ता है।

मालदीव की स्थिति चिंता का कारण है। हम हिंद महासागर में अस्थिरता नहीं देख सकते। वहां स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति को भारतीय उच्चायोग में शरण लेनी पड़ी। इस समस्या का जल्द समाधान करने की भारत की इच्छा समझी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम स्थिति को उस हद तक ले जाने में कामयाब रहेंगे जिससे मालदीव में सामान्य रुप से लोकतंत्र बहाल हो जाए।

महिला

भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत है। इसमें कोई शक नहीं है कि समाज में उनसे भेदभाव किया जाता है। जन्म से ही समाज उन्हें कमजोर समझता है। हमने संवैधानिक रुप से उन्हें समानता की गारंटी दे रखी है लेकिन भारत में लोगों को अपना दिमाग बदलना होगा। समाज में महिलाओं को बराबर मानने के लिए मानसिक सोच में बदलाव लाने की जरुरत है। दिल्ली में बलात्कार और हत्या की हाल की घटना और बाकी जगहों पर भी घटी कुछ ऐसी घटनाओं के कारण हमारे सिर शर्म से झुक गए हैं। हमारे कानून की खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन हमारा पुलिस तंत्र, जांच तंत्र और समाज, खासतौर से पुरुषों के रवैये में भारी बदलाव की जरुरत है। हाल की घटनाओं से साफ है कि हम शिष्टाचार के पैमाने पर नीचे फिसल गए हैं। हमारी परीक्षा हो रही है। शिष्टाचार को हम खो नहीं सकते।

यूपीए होने के रास्ते पर है। वह अपने पीछे अर्थव्यवस्था को खराब हाल में छोड़कर जा रही है। उसने राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। निराशा के इस माहौल में वंशवादी लोकतंत्र की बिसात पर भारत को आगे बढ़ाने की यूपीए की उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। भारत के असली मोल का तभी अहसास होगा जब वंशवाद के ऐसे करिश्मों को धाराशायी कर दिया जाए। क्षमता और वंशवाद के आधार पर भारत को बदलने वालों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को सभी देखेंगे।

एक नाकाम और भ्रष्ट सरकार देश को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

(आर.के. सिन्हा)

सचिव

भाजपा संसदीय कार्यालय